International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

डिजिटल युग में महिलाओं का सशक्तिकरण, अवसर, चुनौतियाँ और सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री विश्लेषण

प्रियंका[1] एवं डॉ. विद्या पंचागंम[2]

1. पीएचडी शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
2. प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय उतई, दुर्ग (छ.ग.)

शोध सार :–

इक्कीसवीं सदी का डिजिटल युग सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक संबंधों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में व्यापक परिवर्तन का वाहक बना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने महिलाओं के जीवन में नई संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। प्रस्तुत शोधपत्र पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों–राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों, सरकारी नीति दस्तावेजों, जनगणना आँकड़ों, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों तथा शोध आलेखों–के विश्लेषण पर आधारित एक वैचारिक–विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, उपयोग और उससे उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन करना है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि डिजिटल मंचों ने शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन तथा राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। परंतु डिजिटल विभाजन, लैंगिक असमानता, साइबर उत्पीड़न, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिबंध और संरचनात्मक पितृसत्ता अब भी सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं।

अध्ययन में 'डिजिटल इंडिया', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'स्टैंड अप इंडिया' जैसी पहलों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है तथा यह प्रतिपादित किया गया है कि डिजिटल सशक्तिकरण को सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के व्यापक ढाँचे में समझना आवश्यक है। निष्कर्षतः डिजिटल युग महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी शक्ति रखता है, किंतु समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु समावेशी नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य हैं।

मुख्य शब्द :– डिजिटल सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता, डिजिटल विभाजन, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक परिवर्तन, महिला उद्यमिता–

प्रस्तावना :–

डिजिटल क्रांति ने विश्व समाज को 'नेटवर्क समाज' में रूपांतरित कर दिया है। इंटरनेट, मोबाइल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास ने सामाजिक संपर्क, आर्थिक उत्पादन और राजनीतिक संवाद के स्वरूप को बदल दिया है। भारत में डिजिटल परिवर्तन विशेष रूप से 2014 के बाद तीव्र हुआ, जब Digital India कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना का विकास, सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण था।

महिला सशक्तिकरण भारतीय सामाजिक विमर्श का केंद्रीय विषय रहा है। संविधान में समानता के अधिकार के बावजूद, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय निर्माण में समान अवसर प्राप्त नहीं हुए। डिजिटल तकनीक इस ऐतिहासिक असमानता को चुनौती देने का माध्यम बन सकती है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या डिजिटल

संसाधनों की उपलब्धता वास्तव में महिलाओं को सशक्त बना रही है, या फिर यह नई असमानताओं को जन्म दे रही है?

यह शोध इसी प्रश्न का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्ययन की प्रासंगिकता :–

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु लैंगिक अंतर अभी भी स्पष्ट है। National Statistical Office (2021) की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की इंटरनेट पहुँच पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

NITI Aayog (2022) ने अपनी रिपोर्ट में डिजिटल समावेशन को महिला सशक्तिकरण की पूर्वशर्त बताया है। इसी प्रकार UN Women (2020) और UNESCO (2019) ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल लैंगिक विभाजन को गंभीर चिंता का विषय माना है।

इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल युग में महिलाओं की स्थिति का गहन विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।

साहित्य समीक्षा :–

महिला सशक्तिकरण पर समाजशास्त्रीय साहित्य में पितृसत्ता, लैंगिक विभाजन और संरचनात्मक असमानता को केंद्रीय अवधारणाओं के रूप में देखा गया है। अमर्त्य सेन (1999) ने 'क्षमता दृष्टिकोण' के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि विकास केवल आय वृद्धि नहीं, बल्कि व्यक्तियों की क्षमताओं के विस्तार का प्रश्न है। डिजिटल संसाधनों तक पहुँच महिलाओं की क्षमताओं का विस्तार कर सकती है।

कस्तूरी (2018) ने भारतीय ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता पर अध्ययन करते हुए पाया कि तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव में डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित रह जाता है। Ministry of Electronics and Information Technology की वार्षिक रिपोर्ट (2023) के अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियानों के बावजूद लैंगिक अंतर बना हुआ है।

साइबर उत्पीड़न पर किए गए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन हिंसा महिलाओं की अभिव्यक्ति को सीमित करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जहाँ #MeToo जैसे आंदोलनों को वैश्विक स्वर दिया, वहीं ऑनलाइन ट्रोलिंग और दुष्प्रचार ने नई चुनौतियाँ उत्पन्न कीं।

भारतीय संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के डिजिटलीकरण पर शोध इंगित करता है कि डिजिटल भुगतान और ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने महिला उद्यमिता को नई दिशा दी है।

सैद्धांतिक रूपरेखा :–

यह अध्ययन उदारवादी नारीवाद, संघर्ष सिद्धांत और संरचनात्मक– कार्यात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है।

उदारवादी नारीवाद समान अवसर और संसाधनों तक समान पहुँच की वकालत करता है। डिजिटल तकनीक महिलाओं को शिक्षा और रोजगार में भागीदारी के नए अवसर देती है।

संघर्ष सिद्धांत के अनुसार संसाधनों का असमान वितरण शक्ति असंतुलन को जन्म देता है। डिजिटल विभाजन वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर नई असमानताओं को जन्म दे सकता है।

संरचनात्मक–कार्यात्मक दृष्टिकोण डिजिटल परिवर्तन को सामाजिक व्यवस्था के पुनर्गठन के रूप में देखता है।

डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास :–

ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, सरकारी ई–लर्निंग पोर्टल और डिजिटल विश्वविद्यालयों ने महिलाओं को उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रदान की है। COVID–19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा का महत्व और स्पष्ट हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रदान कर रहे हैं। परंतु उपकरणों की कमी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या बाधक बनी हुई है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था और महिला उद्यमिता :–

ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने गृहिणियों और स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ा है। डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI) ने वित्तीय लेनदेन को सरल बनाया है।

Stand Up India योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को ऋण सहायता दी जाती है।

महिलाओं की डिजिटल भागीदारी से घरेलू आय में वृद्धि और आर्थिक स्वायत्तता में सुधार देखा गया है।

साइबर सुरक्षा और डिजिटल हिंसा :–

साइबर अपराध महिलाओं के लिए गंभीर चुनौती है। ऑनलाइन उत्पीड़न, पहचान की चोरी और निजी डेटा के दुरुपयोग के मामले बढ़े हैं।

डिजिटल सशक्तिकरण तभी सार्थक होगा जब साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए और कानूनी जागरूकता बढ़ाई जाए।

सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक सहभागिता :–

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी का अवसर दिया है। ऑनलाइन अभियानों ने लैंगिक न्याय के मुद्दों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उठाया है।

ई–गवर्नेंस सेवाओं ने महिलाओं को सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुँच प्रदान की है।

विश्लेषण :–

द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि डिजिटल युग महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी संभावनाएँ रखता है। परंतु डिजिटल पहुँच में असमानता, सांस्कृतिक प्रतिबंध और पितृसत्तात्मक मानसिकता सशक्तिकरण की प्रक्रिया को सीमित करती है।

डिजिटल सशक्तिकरण को सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की व्यापक प्रक्रिया से जोड़ना आवश्यक है।

निष्कर्ष :–

डिजिटल युग महिलाओं के लिए अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है। यदि डिजिटल समावेशन को लैंगिक दृष्टिकोण से लागू किया जाए तो यह सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन सकता है।

महिलाओं की डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा जागरूकता और ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची :–

1. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
2. Government of India. (2015). Beti Bachao Beti Padhao scheme guidelines. Ministry of Women and Child Development.
3. Bhatia, S. (2018). Digital literacy and women empowerment in rural India. Journal of Gender Studies, 27(3), 345–360.
4. Kasturi, L. (2018). ICT and women's empowerment in India. Indian Journal of Social Development, 18(2), 145–160.

5. UNESCO. (2019). I'd blush if I could: Closing gender divides in digital skills through education. UNESCO Publishing.
6. UN Women. (2020). Gender equality in the digital age. United Nations.
7. World Bank. (2021). Women, business and the law 2021. World Bank Publications.
8. National Statistical Office. (2021). Household social consumption on education in India. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
9. NITI Aayog. (2022). Digital inclusion and women empowerment in India. Government of India.
10. Ministry of Electronics and Information Technology. (2023). Digital India annual report 2022–23. Government of India.